



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2005/अग्रहायण 18, 1927

No. 506]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2005/AGRAHAYANA 18, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2005

सं. 101/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 716(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 290312 00 के अंतर्गत आने वाले यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए मिथाईलीन क्लोराइड (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित अपनी प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं. 17/1/2001-डीजीएडी, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

(क) यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए मिथाईलीन क्लोराइड का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके कारण पाटन हुआ था;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

(ग) यह क्षति संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण हुई थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 27 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 27 मार्च, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/2003-सीमाशुल्क, तारीख 27 मार्च, 2003 द्वारा संबद्ध माल पर, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अब अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 17/1/2001-डीजीएडी, तारीख 14 अगस्त, 2003 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 18 अगस्त, 2003 में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

(क) संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए मिथाईलीन क्लोराइड का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया था जिसके कारण पाटन हुआ था ;

(ख) घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति हुई थी;

(ग) यह क्षति संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण हुई थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा.का.नि. 827(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2003 के

अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 20 अक्टूबर, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 157/2003-सीमाशुल्क, तारीख 20 अक्टूबर, 2003 द्वारा संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, अधिसूचना सं. 15/28/2004-डीजीएडी, तारीख 31 अक्टूबर, 2005 में प्रकाशित अपने अंतिम मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि —

(क) यूरोपीय संघ के मूल को अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं को उनके सामान्य मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्यात हुआ पाया गया है और ये अपाटित हैं।

(ख) जांच अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका से कोई निर्यात नहीं हुआ है।

(ग) सिंगापुर से निर्यातों जो बहुत कम मात्रा में हैं, को भारत को उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात हुआ पाया गया है और ये पाटित हैं।

(घ) संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति नहीं हुई है।

(ङ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।

और संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध माल के सभी आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 827(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2003 के तहत प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 157/2003-सीमाशुल्क, तारीख 20 अक्टूबर, 2003 को, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रांत पूर्व की गई हैं या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करती है।

[फा. सं. 354/4/2003-टीआरयू (पार्ट-I)]

अजय, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2005

No. 101/2005-CUSTOMS

**G.S.R. 716(E).**—Whereas in the matter of import of Methylene Chloride (hereinafter referred to as the subject goods), falling under the tariff item 2903 12 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from the European Union, South Africa and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority in its preliminary findings vide notification No. 17/1/2001-DGAD, dated the 24th December, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th December, 2002, had come to the conclusion that—

- Methylene Chloride, originating in or exported from the subject countries, had been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- the domestic industry had suffered material injury;
- the injury had been caused by imports from the subject countries/territory;

And Whereas on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 49/2003-CUSTOMS, dated the 27th March, 2003, G.S.R. 248(E), dated the 27th March, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th March, 2003;

And whereas the designated authority, in its final findings vide notification No. 17/1/2001-DGAD, dated the 14th August, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th August, 2003, had come to the conclusion that—

- Methylene Chloride, originating in or exported from the subject countries, had been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- the domestic industry had suffered material injury;

(c) material injury has been caused by imports from the subject countries/territory;

And Whereas on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed final anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 157/2003-CUSTOMS, dated the 20th October, 2003, G.S.R. 827(E), dated the 20th October, 2003 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th October, 2003;

And Whereas the designated authority, in its final findings in mid-term review, vide notification No. 15/28/2004-DGAD dated the 31st October, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, part I, Section I, dated the 31st October, 2005, has come to the conclusion that—

- (a) Subject goods, originating in or exported from the European Union are found to be exported at above their normal value and are undumped;
- (b) no imports have taken place from South Africa during the period of investigation;
- (c) volume of exports from Singapore, which is insignificant (merely 0.33% of total imports), has been found to be exported to India below their normal value and are dumped;
- (d) the domestic industry has not suffered material injury due to imports from subject countries;
- (e) and discontinuation of anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries is not likely to lead to recurrence of dumping or injury to the domestic industry;

and has recommended discontinuation of the anti-dumping duty imposed on imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), and Sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975, read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 157/2003-CUSTOMS, dated the 20th October, 2003, G.S.R. 827(E), dated the 20th, October, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th October, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/4/2003-TRU-(Pt.-D)]

AJAY, Under Secy.